



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

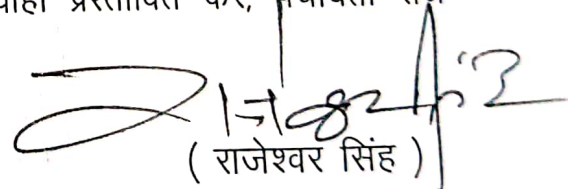
क्र0एफ.4(3)निर्देश/विधि/पंरा/2020/3618

दिनांक : 02-6-2020

1. जिला कलेक्टर,
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति,  
समस्त (राजस्थान)।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कतिपय प्रकरणों में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला जन-प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति/निकट सम्बन्धी/रिश्तेदार या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा कार्यालय का कार्य सम्पादित किये जाने/बैठक आयोजित किये जाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया/हस्तक्षेप किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आपका ध्यान विभागीय आदेश क्र0 359 दिनांक 26.2.2010 (प्रति संलग्न है।) की ओर आकर्षित कर लेख है कि पंचायती राज संस्था के निर्वाचित सदस्य/पदाधिकारी द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है तो यह कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थता एवं दुराचरण की श्रेणी में आता है और किसी पंचायती राज संस्था में ऐसा पाये जाने पर सम्बन्धित महिला सदस्य/पदाधिकारी के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-38 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के प्रकरणों में सहयोग करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध भी सीसीए नियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

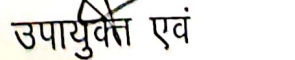
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप पंचायती राज संस्थाओं में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दें। यदि कहीं ऐसा पाया जाये तो सम्बन्धित निर्वाचित जन-प्रतिनिधि एवं सहयोग करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर, पंचायती राज विभाग को अवगत करावें।

  
(राजेश्वर सिंह)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि:-

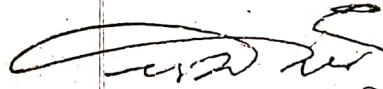
1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0 राज, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अधिकारीगण, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. एसीपी, पंचायती राज विभाग को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने के लिये।

  
उपायुक्त एवं

संयुक्त शासन सचिव(प्रथम)

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं में चुने गये महिला जन-प्रतिनिधि स्वयं कार्यालय में नहीं बैठकर उनकी कुर्सी पर उनके निकट के संबंधी/रिश्तेदार कार्यालय का कार्य सम्पादित करते हैं, संस्था के कार्य में उनका पूर्ण हस्तक्षेप रहता है। यह स्थिति कदापि उचित नहीं है।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि चुने हुए प्रतिनिधि स्वयं उनकी कुर्सी पर बैठे तथा स्वयं के स्तर पर कार्य सम्पादित करें। स्वयं के द्वारा कार्य संचालन नहीं कर यदि अपने रिश्तेदार/सम्बन्धी द्वारा कार्य सम्पादित कराया जाता है तो यह कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थता एवं दुराचरण की श्रेणी में आता है। किसी पंचायती राज संस्थाओं में ऐसा व्यवहार पाया जाता है तो संबंधित महिला चेयरपरसन /आफिस बेरियर के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। साथ ही इस व्यवहार में सहयोग करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध भी सीसीए नियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी।



प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1:-निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री महोदय राज0 जयपुर।
- 2:-निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज0 जयपुर।
- 3:-निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज0 जयपुर।
- 4:-निजी सचिव, मुख्य सचिव, महोदय राज0 जयपुर।
- 5:-निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
- 6:-संभागीय आयुक्त, समस्त।
- 7:-जिला कलक्टर, समस्त।
- 8:-मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
- 9:-विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।

शासन उप सचिव (विधि)

राज0 जयपुर।